



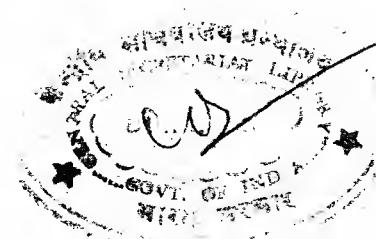
आरत का गज़तपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—पार्ट 1
PART I—Section 1

शासकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 249]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 15, 1992/अग्रहायण 24, 1914

No. 249] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 15, 1992/AGRAHAYANA 24, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वाली जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be field as a
separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 88/पी एन/92-97

नई दिल्ली, दिनांक 15 दिसम्बर, 1992

विषय:—रुपया भुगतान क्षेत्र वाले देशों से अपरिष्कृत हीरों
का आयात।

फाइल सं. 12/11/92-ई पी सी.—वाणिज्य मंत्रालय की
सार्वजनिक सूचना सं. 55/(पी एन)/92-97 दिनांक 25
सितम्बर, 1992 की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. पूर्वोक्त सार्वजनिक सूचना सं. 55/(पी एन)/92-97
दिनांक 25-9-1992 के पैरा 2 में निहित प्रावधानों का
अधिक्रमण करते हुए यह तय किया गया है कि नियर्ति-
आयात नीति, 1992-97 के पैरा 21 के प्रावधानों के तहत
रुपया भुगतान क्षेत्र वाले देशों से आयात करने के लिए
ज्ञारी किए गए एकिज्य स्क्रिप्ट या आर ई पी लाइसेंसों का

इस्तेमाल नीचे बताई गई प्रक्रिया/नीति के अनुसार उपरा
भुगतान क्षेत्र वाले देशों से "प्रापरिष्कृत हीरों" के आयात
के लिए सामान्य मुद्रा क्षेत्र वाले देशों को तराशे हुए तथा
परिष्कृत हीरों के नियांत्र के उद्देश्य के लिए किया जा सकता
है:—

- (1) रुपया भुगतान क्षेत्र वाले देशों से अनुमित अपरिष्कृत
हीरों का कुल सकार आयात 6 करोड़ रुपये से
अधिक नहीं होगा और ऐसे आयात 31 दिसम्बर
1992 तक ही अनुमेय हैं;
- (2) आयात केन्द्र बम्बई तोगशुल्क के जरिये अनुमित
होगा;
- (3) संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-नियांत्र, बम्बई तद्द
लाइसेंस जारी करने के लिए लाइसेंसिंग प्राविकारी
होगा;

(4) वैध एकिजन स्किप/ग्रार ई पी लाइसेंसों को रत्न और आभूषण नियंत्रित संवर्धन परिषद / भारतीय नियंत्रित संगठन भवासंबंध द्वारा जारी किए गए पंजीकरण-सह-संस्थाता प्रमाणपत्र की एक प्रति नया अपेक्षित आवेदनशुल्क सहित संयुक्त मुद्रा नियंत्रक, आयात-नियंत्रित, बम्बई के मुद्रुद कर दिया जाएगा;

(5) संयुक्त मुद्र्य नियंत्रक आयात-नियंत्रित, बम्बई वैध एकिजन स्किप/ग्रार ई पी लाइसेंसों को निरस्त करेंगे तथा एक तर्द्ध लाइसेंस जारी करेंगे जो कि केवल रूपया भुगतान क्षेत्र वाले देशों से अपरिष्कृत हीरों का आयात करने के लिए वैध होंगे। इस लाइसेंस को केवल भारतीय रूपयों में अधिनामित किया जाएगा;

(6) तर्द्ध लाइसेंस और इसके मद्देद आयात किए गए माल पर “अहस्तान्तरणीय” और “वास्तविक उपभोक्ता” शब्द होंगी;

(7) इस लाइसेंस पर नियंत्रित को नियांत्रित आभार पूरा करना होगा। नियांत्रित आभार 65 प्रतिशत प्रतिपूर्ति के व्युत्प्रक्रम अनुपात में होगा, अर्थात् यदि लाइसेंस रु. 65 के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के लिए जारी किया जाता है तो नियांत्रित आभार का जहाज पर्यंत निशुल्क मूल्य रु. 100 के बराबर अमेरिकी डालरों के रूप में तदर्थ लाइसेंस के जारी होने को तारीख को प्रवत्तिन विनियम द्वारा पर आवासित होगा। विमुक्ति के समय लाइसेंसधारी की वास्तविक हकदारी नियंत्रित और आयात नीति 1992—97 के परिशिष्ट-1 में समस्त नियंत्रित उत्पादों के लिए स्वीकृत्य प्रतिपूर्ति दरों के संदर्भ में पुनः संगणित की जाएगी। इस प्रकार के पुनः संगणन की वजह से यदि लाइसेंसधारी की हकदारी रु. 65 के बराबर अमेरिकी डालर से जैसा कि (उदाहरण में दिया गया है) अधिक बनती है तो ऐसी स्थिति में संयुक्त मुद्र्य नियंत्रक आयात-नियंत्रित, बम्बई अपरिष्कृत हीरों के आयात के लिए 65 रु. से अधिक, जो कुछ भी मूल्य बनता हो, उसके बराबर प्रतिभूति लाइसेंस जारी करेगा;

(8) नियंत्रित सामान्य मुद्रा क्षेत्र के देशों को नियंत्रित करके नियांत्रित आभार की पूर्ति करेंगे। रूपया भुगतान क्षेत्र को किए गए किसी भी नियंत्रित को नियंत्रित नियंत्रित आभार की पूर्ति के लिए नहीं गिना जाएगा;

(9) नियंत्रित आभार की पूर्ति सीमाशुल्क के माध्यम से प्रथम खेप की निकासी की तारीख से 7 माह की अवधि के भीतर की जाएगी;

(10) आयात की प्रथम खेप की निकासी से पूर्व लाइसेंसधारी संयुक्त मुद्र्य नियंत्रक, आयात-नियंत्रित, बम्बई के पास लातिन्यूर्नि एवं गारंटी बंधाव अथवा शिविक-बचनपत्र जैसा भी मापदण्ड हो, विनारितिवाल रूप में नियांत्रित करेगा:—

(क) यदि लाइसेंसधारी का नियांत्रित नियांत्रित एक वर्ड का नहीं है तो लाइसेंस के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर को धनराशि के लिए; अथवा

(ख) यदि लाइसेंसधारी का नियांत्रित नियांत्रित एक वर्ड या इससे अधिक का है लेकिन तोन वर्डों से कम का है तो लाइसेंस के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के 30 % के बराबर की धनराशि के लिए; अथवा

(ग) यदि लाइसेंसधारी तोन वर्डों या इसमें अधिक का नियांत्रित नियांत्रित रहता हो तो एक विधिक-बचनपत्र नियांत्रित करने की अनुमति दी जाए।

3. संयुक्त मुद्र्य नियंत्रक आयात-नियंत्रित, बम्बई तदर्थ लाइसेंसों के नियंत्रित को मानीटर करेगा। वह यह सुनिश्चित करेगा कि इस सार्वजनिक सूचना के अनुसरण में जारी किए गए तदर्थ लाइसेंस का कुल मूल्य 6 करोड़ रुपए से अधिक या उसकी अवधि 31 दिसंबर, 1992 से अधिक नहीं होंगे। जब कभी इन सीमाओं में से कोई सीमा पहले पूरी हो जाए तो आगे कोई लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे।

4. सार्वजनिक सूचना सं. 55(पी/एन)/92—97 दिनांक 25-9-1992 के अनुसरण में यदि कोई आयात पहले हो किया गया हो तो उसके संबंध में भी उपर्युक्त प्रावधान लागू होंगे।

5. इसे सार्वजनिक हित में जारी किया जाता है।
सी.के. मोदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

Public Notice No. 88(PN) | 92—97

New Delhi, the 15th December, 1992

Subject :—Import of Rough Diamonds from RPA countries.

File No. 12/11/92-EPC.—Attention is invited to the Ministry of Commerce Public Notice No. 55(PN) | 92—97 dated 25th September, 1992.

2. In supersession of the provisions contained in para 2 of the aforesaid Public Notice No. 55(PN) | 92—97 dated 25-9-1992, it has been decided that in terms of the provisions of para 21 of the Export and Import Policy, 1992—97, Eximscripts or REP licences issued for the purpose of imports from RPA countries can be utilised for import of “Rough Diamonds” from RPA countries, for the purpose of export of cut and polished diamonds to GCA countries, in accor-

dance with the policy/procedure indicated below :—

- (i) the total overall import of rough diamonds permitted from RPA countries shall not exceed Rs. 6 crores and such imports are permitted upto 31st December, 1992;
- (ii) the imports shall be allowed only through the Bombay Customs;
- (iii) the Jt. CCI&E, Bombay shall be the licensing authority for issuing the ad-hoc licences;
- (iv) the valid Exim Scrip|REP licences shall be surrendered to Jt. CCI&E, Bombay, along-with a copy of the Registration-cum-membership certificate issued by the Gem and Jewellery Export Promotion Council|Federation of Indian Export Organisations and the requisite application fee;
- (v) the Jt. CCI&E, Bombay shall cancel the valid Exim Scrip|REP licences and shall issue an ad-hoc licence which will be valid for import of rough diamonds from RPA countries only. This licence shall be denominated in Indian Rupees only;
- (vi) the ad-hoc licence and the goods imported against it shall carry "non-transferable" and "Actual user" conditions;
- (vii) on this licence, the exporter shall be required to fulfil the export obligation. The export obligation shall be in the inverse ratio of 65 per cent replenishment, i.e., if the licence is issued for a c.i.f. value of Rs. 65, the f.o.b. value of export obligation shall be in terms of US Dollars equivalent to Rs. 100 based upon the exchange rate prevalent on the date of issue of the ad-hoc licence. At the time of redcmption, the actual entitlement of the licensee shall be recalculated with reference to the replenishment rates admissible for the corresponding export products in Appendix I of the Export and Import Policy, 1992—97. Due to such re-calculation, if the licensee's entitlement comes to more than US Dollars equivalent to Rs. 65 (as in this example) the Jt. CCI&E, Bombay shall issue a Replenishment licence for a value equivalent to what-

ever is in excess of Rupees 65 for import of rough diamonds;

- (viii) the exporter shall fulfil the export obligation by making exports to GCA countries. Any export made to RPA country shall not be counted towards fulfilment of the prescribed export obligation;
- (ix) the export obligation shall be fulfilled within a period of seven months from the date of clearance of first consignment through Customs;
- (x) before the clearance of first consignment of import, the licensee shall execute an indemnity-cum-guarantee bond or legal undertaking, as the case may be, with the Jt. CCI&E, Bombay in the following manner :—
 - (a) for an amount equal to 50 per cent of the cif value of the licence if the licensee does not have export performance of minimum one years, or
 - (b) for an amount equal to 30 per cent of the cif value of the licence, if the licensee has an export performance of one year or more but less than three years; or
 - (c) a legal undertaking may be permitted to be executed if the licensee has export performance of three years or more.

3. The Jt. CCI&E, Bombay shall monitor the issue of ad-hoc licences. He shall ensure that the total value of ad-hoc licences issued in pursuance of this Public Notice shall not exceed Rs. 6 crores on 31st December, 1992. As and when either of these two limits is reached earlier, no further licences shall be issued.

4. The aforesaid provisions shall also apply in respect of the imports, if any, already made in pursuance of Public Notice No. 55(PN)|92-97 dated 25-9-1992.

5. This issues in public interest.

C. K. MODI, Director General of
Foreign Trade

